

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 107/16

GCMS NO 2016/00087

1. जगनी
2. हल्की
3. भौती
4. कमला पुत्रियान बुध्दू जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली
अपीलांट

बनाम

1. हरि
2. प्रहलाद पिसरान बुध्दू
3. पांची बेवा बुध्दू जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली
4. अशफाक जहमद पुत्री बुध्दू जाति माली निवासी निवासी बाजीदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली
रेस्पों




अपील विरुद्ध मु0नं0 4/16 निर्णय दिनांक 3.10.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली)
अभिभाषक/अपीलांट श्री अशफाक जहमद
अभिभाषक रेस्पों श्री मुकेश कुमार शर्मा

दिनांक 19.02.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 3.10.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली पेश की है।


अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांटगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा नं0 781,782,783,784,780 वाके पांडे के कुआ करौली तहसील व जिला करौली में स्थित है। जिसके रिकार्डेड खातेदार पक्षकार है। सायलान व गैरसायलान दर्ज प्रार्थना पत्र आपस में भाई बहिन है व मां है तथा विवादित आराजीयात में जो हिस्सा रिकार्ड में बुध्दू के वारिसान के रूप में हरि, प्रहलाद, जगनीबाई, हल्की, द्रोपती व भौती व कमल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसमें हम बराबर बराबर के हिस्सेदार है व काबिज है। गैरसायलान 1 ता 4 के दिल में बदनियती आने लगी और वह पैसे के लालच में हम सायलान हकूक से इंकार करने लगे तथा हम सायलान द्वारा बंटवारे की कहने पर बंटवारे से इंकार कर दिया तथा जमीनो को बेचने की धमकी दे दी। जिसके कारण सायलान दिनांक 8.2.16 को इजलास श्रीमान में दावा बंटवारा व हुक्म इम्तनाई दवामी पेश किया जिसका उनवान जगनी बनाम हरि वगैरे है। जिसका मु0नं0 3/16 है। जिसमें नोटिस हरि वगैरे को जारी किये गये है। उक्त दावे के नोटिस गैरसायलान को मिलने पर उनके द्वारा भूमि को रहन बय करने की धमकी दी गई तथा भू माफियत धक्कर काट रहे है। पक्षकारान के मध्य अभी बंटवारा नही हुआ है तथा बंटवारे से पूर्व ही यदि गैरसायलान ने अपना हिस्सा किसी दीगर अजनबी व्यक्ति को रहन बय कर दिया तो अशांति फैलने व मल्टी पिलिस्टी ऑफ सूट बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन बय कब्जा मुन्तकिल नही करने हेतु हुक्म स्टे जारी किया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायलान को इस अमर से पाबंद किया जावे कि यह बंटवारे से पूर्व वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय व मुन्तकिल किसी प्रकार से नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज, रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 100/-रूपये के अनरजिस्टर्ड स्टाम्प जिसका कानूनी कोई महत्व नहीं है को मानकर फैसला हाजा सादिर किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांटगण रिकार्ड खाली है तथा बुधू के वारिसान के बतौर कलेक्टर साहब के आदेश से खातेदार बने हैं तथा संभागीय आयुक्त के यहाँ हरि, प्रहलाद ने मिली बात कर धोखे में डालकर लिखापट्टी कर हमारे अंगूठा के फौजदारी में करा लिया जिसकी कार्यवाही रेवेन्यू बोर्ड में चल रही है। संभागीय आयुक्त के व गैर कानूनी कागज को रिलीज डीड गैर कानूनी तौर पर माना है। बंटवारा हुए वगैर डीड के वगैर हकूक मौजूदा हालात में नहीं होते हैं इस तथ्य को अदालत मातहत ने किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अंतिम निर्णय की फाईण्डिंग दे दी है जबकि स्टे की स्टेज पर अंतिम निर्णय जैसा फैसला देना चाहिए। अपीलांटगण अनपढ़ व गरीब है ऐसी सूरत में अदालत मातहत ने रिकार्ड को गौर नहीं किया तथा प्रथम दृष्टया मामला सायलान/अपीलांटगण के हक में होने व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के हक में तमाम तथ्य जो टी आई स्टेज पर दिये वह दावे में तय होते हैं परन्तु स्टे स्टेज पर ही अंतिम निर्णय करने में कानूनी भूल की है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.10.16 को अपास्त किया जावे तथा मौके एवं रिकार्ड की दायरी दावे की स्थिति को यथावत रखा जावे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण/सायलान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को हडपने व रूपये ऐठने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था। रेस्पों द्वारा खसरा न० 801,802,809 व 822 का विक्रय करते समय रेस्पों द्वारा अपीलांटगण को 3-3 लाख रूपये देकर 100/-रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तहरीर व तकमील कराया है जिस पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा चालाकी पूर्वक अब हमारे बचे हुए खसरा न० की भूमि को हडपने की बदनियती से यह झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से तहत खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण/सायलान द्वारा रेस्पों की खातेदारी की भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर करौली के यहाँ एक अपील पेश की थी जिसे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड की गई थी। तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 17.11.2011 को अपील की सुनवाई कर सायलान/अपीलांटगण के पक्ष में नामा० खोले जाने के आदेश दिये गये जिसकी अपील संभागीय आयुक्त के यहाँ की गई जिसमें अपीलांट/सायलान द्वारा दिनांक 23.2.12 को राजीनामा पेशकर बुधू की सम्पत्ति में से अपना हक त्यागकर सम्पूर्ण हक रेस्पों के हक में त्याग कर दिया। जिस पर संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.3.16 को जिला कलेक्टर करौली का निर्णय दिनांक 24.10.11 व तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 17.11.11 को निरस्त कर नामा० संख्या 793 दिनांक 14.8.96 को यथावत रखने के आदेश दिये गये। इस प्रकार उक्त आराजीयात में अपीलांटगण का कोई हक हकूक शेष नहीं है। अपीलांट/सायलान द्वारा बेईमानी पूर्वक झूठे तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई है। संभागीय आयुक्त महोदय के यहाँ विचाराधीन


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के दौरान उक्त आराजीयात को बेचान राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र हुकम चंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी इन्द्रा कालोनी करौली को किया गया उक्त बयनामा को निरस्त कराने हेतु जिला जजी करौली के यहाँ गैरसायलान द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पों/गैरसायलान द्वारा राजेन्द्र कुमार शर्मा को दिनांक 5.1.15 को हम रेस्पों/गैरसायलान हरि, प्रहलाद, पाँची द्वारा 23 लाख 50 हजार रुपये देकर राजीनामा किया और राजेन्द्र कुमार शर्मा के हक में हुए बयनामा को निरस्त कराया। राजेन्द्र कुमार शर्मा बयनामा कराते समय जो विक्रय कीमत 13 लाख 50 हजार रुपये प्राप्त किये थे वे भी राशि अपीलांटगण के पास है। राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा से जो राजीनामा रेस्पों द्वारा किया गया है उस आधार पर भी उक्त आराजीयात में अपीलांटगण का कोई हक हकूक शेष नहीं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांटगण द्वारा किये गये राजीनामा तथ्यों का अवलोकन किया जाकर ही सायलान/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप में पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत अपीलांटगण द्वारा रेस्पों के पक्ष में 100/-रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा लिखा गया है। जिसमें अपने हिस्से की भूमियों को रेस्पों/गैरसायलान को नकद रुपये लेकर सहमति दी गई है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत अपीलांटगण/सायलान द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहाँ दिनांक 23.2.23 को उक्त आराजीयात में से अपना हिस्सा त्याग करने का भी राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामा तस्दीक हुआ है। जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध राजीनामा से होती है जिस पर विधिवत रूप से अपीलांटगण के फोटोग्राफ चस्पा है। तत्पश्चात माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा राजीनामा अनुसार पूर्व नामा संख्या 793 दिनांक 14.6.96 को यथावत रखा गया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध छाया प्रति निर्णय दिनांक 18.3.16 से होती है। अपीलांटगण का बार बार कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। जबकि अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात रेस्पों के नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांटगण द्वारा किये गये राजीनामे के दृष्टिगत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नहीं आने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 4/16 में पारित निर्णय दिनांक 3.10.16 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपीलांटगण प्रधिकारी
सवाई माधोपुर